RNI No.: MAHHIN/2016/71344

संकल्प प्रभात

संपादक - अनिल बी. तिवारी

4 | मराठी फिल्म 'फरफट' की शूटिंग पूरी..!

● वर्ष- ०५ ● अंक- ०९ ● मुंबई, सोमवार १९ जुलाई २०२१ से रविवार २५ जुलाई २०२१ ● पृष्ठ-८ ● मूल्य-५रु

काबुल को अफगानिस्तान से काट सकता है तालिबान | 8

संक्षिप्त खबरें

असली RT PCR निकालकर फिर बनाने लगे फर्जी रिपोर्ट

मुंबई- अब किसी को नौकरी देने से पहले भी कुछ कंपनियां या तो वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट मांग रही हैं या RT PCR टेस्ट की रिपोर्ट। अडिशनल सीपी सत्यनारायण चौधरी ने एनबीटी को बताया कि कोलाबा पुलिस ने फर्जी RT PCR रिपोर्ट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर दो लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल, शांतिलाल मिनारिया

की मुंबई में जॉब लगी, तो उसके मालिक ने उससे RT PCR की रिपोर्ट मांगी। उसने दो-तीन दिन में दक्षिण मुंबई की एक प्राइवेट कंपनी से यह रिपोर्ट लाकर दे दी। वेरिफिकेशन के लिए यह रिपोर्ट संबंधित लैब को भेजी, तो वहां से बताया गया कि यहां से ऐसे किसी व्यक्ति को RT PCR रिपोर्ट नहीं जारी की गई है।

नई पार्किंग नीति का पहला कदम, बीएमसी के तीन वॉर्ड में की गई है नई व्यवस्था

मुंबई- बीएमसी ने पुरानी पार्किंग नीति में संसोधन करके नई पार्किंग नीति तैयार करने के दृष्टि से पहला कदम बढ़ाया है। पूरे मुंबई के लिए एक ही नीति तैयार न करते हुए स्थानीय जरूरत के अनुसार नीति तैयार की जाएगी। इसका पहला प्रयोग डी, के- पश्चिम और एस वॉर्ड में किया जा रहा है। इसे बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने भी हरी झंडी दी है। पार्किंग स्थल में ही पिक ऐंड ड्रॉप, सामानों की लोडिंग-अनलोडिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। स्थानीय लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर पार्किंग की रूपरेखा बनाई जाएगी। इसके लिए वहां के लोगों से चर्चा भी की जाएगी। मुंबई शहर के लिए स्वतंत्र पार्किंग प्राधिकरण बनाया गया है।

मानसून सत्र के लिए सरकार के एजेंडे में कुल ३१ बिल

१९ जुलाई से शुरू होने जा रहे संसद के मानसून सत्र में कृषि कानूनों, किसान आंदोलन, महंगाई, कोरोना की दूसरी लहर और भारत चीन सीमा तनाव जैसे मुद्दों पर तो सरकार और विपक्ष में तकरार होने की उम्मीद है। सरकार कुछ ऐसे बिल भी पेश करेगी, जिन पर नोंक झोंक होने की संभावना है।

सरकार के मुताबिक इस सत्र में वो कुल ३१ बिलों को चर्चा के बाद पारित करवाना चाहती है। इनमें २० नए बिल हैं। २० नए बिलों में ६ बिल ऐसे हैं जो अध्यादेश के बदले पेश होंगे। अध्यादेश के बदले पेश होने वाले बिलों में Insolvency & Bankruptcy Code Bill, The Essential Defence Services Bill और Commission for Air Quality Management in NCR & adjoining areas Bill शामिल हैं। इनमें आवश्यक रक्षा सेवा बिल पर संसद में बवाल हो सकता है। इस बिल में सेना के लिए हथियार, गोला बारूद और यूनिफॉर्म बनाने वाले देशभर के

(शेष पृष्ठ ७ पर)

सर्वदलीय बैठकः सरकार संसद में विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा के लिए तैयार

पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मानसून सत्र के पूर्व ऑल पार्टी मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में ३३ दलों के ४० से अधिक नेताओं ने शिरकत की। इस मीटिंग में नेताओं ने सुझाव दिया कि किन विषयों पर चर्चा की जानी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मीटिंग के बाद बताया कि पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष सहित सभी प्रतिनिधियों के सुझाव बहुत मूल्यवान हैं। सरकार संसद में विभिन्न मुद्दों पर स्वस्थ एवं सार्थक चर्चा के लिए तैयार है। बैठक के बाद शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि आज सभी पार्टियों ने कहा कि किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा है और इसको हल किया जाए। सदन तब चलेगा जब लोगों के मुद्दों को हल किया जाएगा।

यह सर्वदलीय बैठक संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से एक दिन पहले हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सदन में विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक में मोदी के अलावा रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल और संसदीय कार्यमंत्री जोशी शामिल हुए।

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने भी इस सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन, द्रमुक के तिरुचि शिवा, समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव, बसपा के सतीष चंद्र मिश्र सहित सदन में सभी प्रमुख पार्टियों के नेता उपस्थित रहे।

(शेष पृष्ठ ७ पर)

पंजाब कांग्रेस के नए 'कैप्टन' बने नवजोत सिंह सिद्धू, प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिली

नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया है। अब वे सुनील जाखड़ की जगह लेंगे। इसके साथ ही संगत सिंह गिलजियां, कुलजीत नागरा, पवन गोयल और सुखविंदर डैनी कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए नवोजत सिंह सिद्धू के नाम पर मुहर लगा दी। आने वाले समय में सिद्धू के सामने कई तरह की चुनौतियां होंगी, जिसका उन्हें सामना करना होगा।

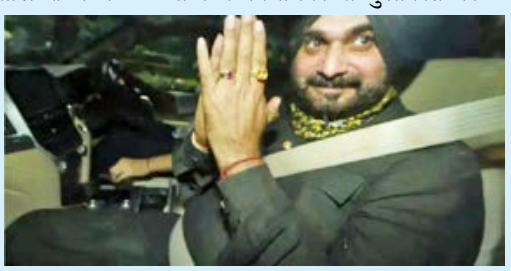

बता दें कि पिछले कुछ दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान मिल सकती है। खबरें ये भी सामने आईं कि सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के संभावित फैसले से सीएम अमरिंदर नाराज हैं। लेकिन आखिरकार सिद्धू ये 'मैच' जीत गए। यहां तक की रविवार को दिल्ली में कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा के घर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह कैंप के सांसदों की एक बैठक भी हुई।

कैप्टन कैंप के पंजाब कांग्रेस सांसदों ने सिद्धू को 'जोकर' तक बताया था और मांग की थी कि उन्हें प्रदेश में पार्टी की कमान नहीं दी जाए। वहीं, सिद्धू ने रविवार को पटियाला, खन्ना और जालंधर में पार्टी के विधायकों से मुलाकात की जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। सिद्धू ने सबसे पहले घनौर के विधायक मदन लाल जलालपुर से उनके आवास पर मुलाकात की। जलालपुर के आवास पर कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, विधायक बरिंदरमीत सिंह पाहरा और दर्शन बराड़ भी मौजूद रहे। सिद्धू ने शूतराना विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्मल सिंह से भी मुलाकात की। बाद में उन्होंने खन्ना के विधायक गुरकीरत सिंह कोटली और पायल के विधायक लखवीर सिंह लाखा से भी मुलाकात कर सभी को अपने पक्ष में लामबंद किया।

संपादकीय...

मुंबई को डुबोता भ्रष्टाचार?

मानसून भौगौलिक तौर पर महाराष्ट्र के तटवर्ती कोंकण इलाके में आता है। इस इलाके में महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों से ज्यादा ही बारिश हर साल होती है। मुंबई में हर साल औसत २५१४ मिलीमीटर बारिश होती है। समुंदर की हाई टाईड- क्योंकि मुंबई अरब सागर के किनारे बसी है, इसलिये इसमें समुंदर भी अपनी एक भूमिका निभाता है। वैसे तो समुंदर में रोजाना ज्वार और भाटा आता है। लेकिन जब ज्वार यानी कि हाई टाईड साढे ४ मीटर से ऊपर की हो तो वो मुंबई के लिए मुसीबत का संकेत है। भारी बारिश और हाई टाईड का मेल मुंबई को ठप कर देता है क्योंकि हाई टाईड की वजह से मुंबई की सड़कों पर जमा पानी समुद्र में नहीं जा पाता और उलटा समुद्र का पानी शहर में घुसता है। जल निकासी न हो पाने की वजह से सड़कों पर कई फुट तक पानी जमा हो जाता है। मुंबई के बाढ़ग्रस्त होने का एक कारण मीठी नदी भी मानी जाती है। मुंबई शहर के बीचों बीच से एक नदी गुजरती है जिसका नाम मीठी नदी है। यह नदी मुंबई के पवई और विहार तालाब से निकलती है और माहिम में जाकर अरब सागर से मिल जाती है। अब मुसीबत यह हैकि तट के दोनों ओर अतिक्रमण होने के कारण नदी का प्रवाह काफी संकरा हो गया है। प्रदूषण और कचरे ने नदी की गहराई भी कम की है। अब नदी ने नाले की शक्ल ले ली है। भारी बारिश होने पर इस नदी में बाढ़ स्थिति बनती है और पानी आसपास के एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लेता

है। आज़ादी के बाद से मुंबई शहर का काफी विस्तार तो हुआ, लेकिन शहर की बढ़ती आबादी के साथ जल निकासी सिस्टम जस का तस ही रहा। ऐसे में जब इस सिस्टम में क्षमता से ज्यादा दबाव आ जाता है जो कि वह झेल नहीं पाता और शहर में हर जगह पानी ही पानी नज़र आता है। भ्रष्टाचार का खेल - हर साल बीएमसी बजट का करीब ३ फीसदी हिस्सा स्ट्रोम वाटर निकासी के लिये होता है। ९०० करोड रूपये के आसपास बीएमसी इस खर्च के लिये रखती है ताकि बारिश में शहर न डूबे। लेकिन शहर फिर भी डूबता है। आखिर क्यों? इसके पीछे कारण भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार की वजह से यह रकम भी बारिश के पानी की तरह बह जाता है। साल २०१७ में सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में वित्तीय लेनदेन के दौरान गड़बड़ी का आरोप लगाया। आरोप ये लगा कि मुंबई महानगरापालिका की ओर से सीवेज मैनेजमेंट के ठेकदारों को गैरकानूनी तरीके से फायदा पहुंचाया गया। अब ठेकेदारों को फायदा पहुंचेगा तो वे किसे फायदा पहुंचायेंगे इसे बखूबी समझा जा सकता है। जमीनी तौर पर यह बात नजर आती है कि जिन लोगों को नाले की सफाई के लिये ठेका दिया जाता है उनमें से सभी ठेकेदार अपना काम ईमानदारी से नहीं करते। यह उसी का नतीजा है कि नाले ओवरफ्लो होने लग जाते हैं और सड़कें नदियां बनने लग जातीं हैं। बात मुंबई की बारिश की हो तो २६ जुलाई २००५ की प्रलयकारी बारिश का जिक्र होना जरूरी है। उस दिन काले बादल मुंबई में कयामत ले आये थे। २४ घंटों के भीतर ९४४ मिलीमीटर की बारिश पूरे शहर में हो गई थी। एक हजार से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सड़कें, रेल, हवाई जहाज सभी बंद हो गये थे। मुंबई का संपर्क पूरी दुनिया से कट चुका था। आज भी तेज बारिश मुंबई वालों को २६ जुलाई के उस काले दिन की याद दिला देती है।

मुंबई मे करीब २००० किलोमीटर के करीब खुले नाले हैं, और लगभग ४४० किलोमीटर के ढंके हुए नाले हैं और १८६ आउटफॉल हैं, जहां से बारिश के कारण जमा हुआ पानी समंदर में गिरता है। २६ जुलाई २००५ की बारिश के बाद ड्रेनेज सिस्टम का कायाकल्प करने के लिये ब्रिमस्टॉवेड नाम के प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। लेकिन आज भी इस प्रोजेक्ट का काम पूरा नहीं हुआ है और मुंबई अब भी डूब रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत ६ पंपिंग स्टेशन बनाये गए लेकिन भारी बारिश के वक्त ये नाकाम साबित हुए हैं। यही कारण है जिससे मुंबई अपनी भौगौलिक स्थिति, समुद्र में उठने वाले ज्वार-भाटे, कुदरत के साथ खिलवाड़ और भ्रष्टाचार के कारण हर साल डूब जाती है।

पंचायत चुनाव पद्धति में बदलाव जरूरी

राजनीतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझे जाने वाले राज्य उत्तर प्रदेश के हाल में सम्पन्न क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव को बाहुबल और धनबल के जरिए, जिस तरह प्रभावित करने का प्रयास किया जाता रहा हैं, वह लोकतंत्र के लिए घातक है। पंचायतों पर कब्जा जमाने के लिए राजनीतिक दलों और बाहुबलियों की तरफ से हिंसा, अपहरण, पैसे के बल पर पंचायत प्रतिनिधियों की खरीद-फरोख्त, और वोट हासिल करने के लिए अपनाए गए अनैतिक आचरण को दृष्टिगत रखते हुए, अब पंचायत चुनाव की मौजूदा पद्धति में सुधार करना आवश्यक है। आमतौर पर देखा गया है कि क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत अध्यक्षों और विधानसभा एवं लोकसभा के उप-चुनाव में, अपवाद को छोड़ दें तो अब तक सत्तारूढ़ दल ही जीतते आए हैं। उ.प्र. के हाल के क्षेत्र एवं जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में सत्तारूढ़ दल अपने प्रतिनिधियों की कम संख्या के बावजूद जिला पंचायत अध्यक्षों की कुल ७५ सीटों में ६७ पर एवं क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों की कुल ८२६ सीटों में ६२६ सीटें जीतने में कामयाब रही। गौर करने की बात है कि पंचायत चुनाव में सर्वाधिक प्रतिनिधि विपक्षी पार्टी के चुन कर आए थे, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में वे अपने कमजोर चुनावी प्रबंधन के कारण मात्र ५ सीटों पर सिमट कर रह गए। इस बार के जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी ने अपने सहयोगी अपना दल (एस) सहित कुल ६७ सीटों पर कब्जा जमाने में कामयाब रही। जबकि सपा को पाँच, रालोद को एक, जनसत्ता दल को एक और एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी को सफलता मिली है। इसी तरह क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में प्रदेश की कुल ८२६ सीटों मे से भाजपा ६२६ सीटें जीतने में कामयाब हुई। गौरतलब है कि २०१६ में सत्ता में रहते हुए भाजपा की ही तरह समाजवादी पार्टी ने भी पंचायत चुनाव में शानदार सफलता हासिल की थी। इस चुनाव में सपा ने अकेले अपने दम पर जिला पंचायत अध्यक्ष की ६३ सीटों पर कब्जा कर लिया था। उस समय भाजपा को मात्र पाँच, बसपा को चार तथा कांग्रेस और रालोद को एक-एक सीटों पर संतोष करना पड़ा।

पंचायतों पर कब्जा करने के लिए राजनीतिक दलों और बाहुबलियों ने जिस तरह के हथकंडे अपनाए, वह चिंता का विषय है। यह सच है कि इस चुनाव में ऐन-केन प्रकारेण विजय हासिल करने के लिए, नैतिकता को ताक पर रख कर लोकतंत्र की मर्यादा को तार-तार करने का हर संभव प्रयास किया गया। इसके लिए प्रतिनिधियों के अपहरण से लेकर उन्हें इकट्ठा करके प्रदेश के बाहर ले जाने, और उन्हें नजरबंद किए जाने तक का खेल खेला गया। इतना ही नहीं, बताते हैं कि चुनाव में प्रतिनिधियों की जमकर खरीद-फरोख्त भी की गई। जानकार बताते हैं कि एक-एक प्रतिनिधि की कीमत ३० से ५० लाख रुपए लगाई गई। कहीं-कहीं एक-एक करोड़ रुपए देकर प्रतिनिधि खरीदे गए। पंचायत चुनाव में भ्रष्ट तरीके अपनाए जाने का अनुमान इस बात से आसानी से लगाया जा सकता है कि, उ.प्र. में सपा के सबसे अधिक उम्मीदवार और समर्थक चुनाव जीत कर आए, इसके बावजूद भी पार्टी सिर्फ पाँच जिला पंचायत अध्यक्ष चुन कर लाने में सफल हो सकी। सपा की तुलना में भाजपा के कम उम्मीदवार जीते, मगर भाजपा ने अपने मजबूत चुनावी प्रबंधन से ७५ में से जिला पंचायत अध्यक्ष की ६७ सीटें जीत कर प्रदेश में अपना परचम लहरा दिया। इस चुनाव में सर्वाधिक नुकसान सपा को उठाना पड़ा। सपा का आरोप है कि उसके प्रतिनिधियों और उम्मीदवारों को अंतिम समय में भाजपा ने लालच देकर अपने पाले में कर लिया। अपने प्रतिनिधियों को पाला बदलने से रोक पाने में असमर्थ, सपा ने आनन-फानन में कार्रवाई करते हुए अपने ११ जिला अध्यक्षों को बर्खास्त कर दिया। यह भी कम दिलचस्प नहीं है कि शुरुआत में बहुजन समाज पार्टी क्षेत्र एवं जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन जब उसने देखा कि भाजपा ने प्रारम्भ में ही अपने २१ जिला पंचायत अध्यक्षों को निर्विरोध चुनवा लिया, तो बसपा की हिम्मत छूट गई। उसने अपने को चुनाव मैदान से दूर कर लिया। ध्यान रहे कि इस चुनाव में सबसे अधिक दुर्गति कांग्रेस की हुई। उ.प्र. में कांग्रेस इतनी कमजोर हो चुकी है कि वह अपने गढ़ अमेठी और रायबरेली में भी अपने प्रत्याशियों को नहीं जितवा सकी। वैसे देखा जाए तो इस चुनाव में सपा और बसपा को भी कम झटका नहीं लगा है। बसपा ने तो चुनाव मैदान से भाग खड़े होकर किसी तरह अपनी इज्जत बचा ली, मगर कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल सकी। कांग्रेस के चुनाव प्रबन्धकों खास कर उ.प्र. की प्रभारी प्रियंका गांधी को इस पर गंभीर मंथन करना होगा, वरना २०२२ में उ.प्र. में चुनाव जीतकर सरकार बनाने का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का दावा खोखला साबित होगा। कहना न होगा कि पंचायत चुनाव के नतीजे कांग्रेस को उ.प्र. में अपनी जमीनी हकीकत समझने के लिए काफी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में प्रभाव रखने वाले रालोद को पंचायत चुनाव में अपेक्षित सफलता तो हासिल नहीं हुई, लेकिन जयंत चौधरी अपने दादा पूर्व प्रधानमंत्री स्व. चौधरी चरण सिंह और अपने पिता स्व. चौधरी अजित सिंह के गढ़ बागपत जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट जीत कर अपने पूर्वजों की लाज बचाने में अवश्य कामयाब रहे। वहीं प्रतापगढ़ में राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल ने जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट जीत कर जिले में अपना दबदबा बरकरार रखा है। जौनपुर के पूर्व संसाद धनंजय सिंह अपनी पत्नी श्री कला सिंह को जौनपुर जिला पंचायत सीट से विजयी बनाने में सफल हुए। सोनभद्र में अनुप्रिया पटेल का उम्मीदवार विजयी हुआ है।

वरिष्ठ पत्रकार
आनंद शुक्ल

आश्चर्य इस बात पर है कि सपा के गढ़ समझे जाने वाले मैनपुरी, कन्नौज और फिरोजाबाद में भाजपा ने उसे शिकस्त दी है। बलिया, आजमगढ़, संतकबीर नगर, एटा और इटावा में अखिलेश यादव की रणनीति अवश्य कारगर साबित हुई। इन पाँचो सीटों पर सपा को सफलता मिली है। भाजपा को पश्चिमी उ.प्र. के १४ जिलों में १३, ब्रज क्षेत्र के १२ जिलों में ११, कानपुर क्षेत्र के १४ जिलों में १३, अवध क्षेत्र के १३ जिलों में १३, काशी क्षेत्र के १२ जिलों में १० तथा गोरखपुर क्षेत्र के १० जिलों में ७ सीटों पर भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए। इस बार के चुनाव में रामपुर, प्रतापगढ़, उन्नाव और सुल्तानपुर में त्रिकोणीय मुक़ाबला, एटा, सीतापुर और जौनपुर में चतुष्कोणीय और प्रदेश के करीब ४५ जिलों में भाजपा और सपा के बीच सीधा मुक़ाबला देखने को मिला। चुनाव नतीजों को लेकर मीडिया की रिपोर्ट और सत्तारूढ़ दल के नेताओं के बयान आश्चर्यचकित करने वाले हैं। मीडिया के एक वर्ग और भाजपा की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि पंचायत चुनाव के नतीजे २०२२ के उ.प्र. विधानसभा चुनाव का सेमी फ़ाइनल है। चुनाव नतीजों को उ.प्र. के आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़ कर देखना शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता द्वारा न करा कर निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। ये चुनाव बिलकुल अलग पद्धति से कराए जाते हैं। इसलिए इसके जरिए जनमत का सही-सही आकलन कर पाना मुश्किल होता है। सत्तारूढ़ दल के नेताओं को पंचायत चुनावों के संदर्भ में बयान बाजी करने से पूर्व तथ्यों से ठीक प्रकार से अवगत होना आवश्यक है। क्योंकि देखा गया है कि कई वरिष्ठ और अनुभवी नेता भी अपने बयान में, इस बात को प्रमुखता से रख रहे है कि पंचायत चुनाव के नतीजे राज्य सरकार के कार्यों पर मुहर है। जबकि वास्तव में ऐसा नही है। इन चुनावों का विधानसभा और लोकसभा चुनाव पर कोई खास असर नहीं होने वाला।

स्टैन स्वामी के मेडिकल रेकॉर्ड हाई कोर्ट में जमा, पिछले हफ्ते अस्पताल में हुआ था निधन

मुंबई- राज्य सरकार ने दिवंगत पादरी स्टैन स्वामी के चिकित्सा संबंधी ३०० पृष्ठ के दस्तावेज को मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में जमा कर दिए हैं। स्वामी एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में आरोपी थे और मेडिकल आधार पर जमानत याचिका लंबित रहने के दौरान पिछले हफ्ते न्यायिक हिरासत में एक अस्पताल में उनका निधन हो गया था। इस मामले में अब १९ जुलाई को सुनवाई होगी।

मुख्य लोक अभियोजन अरुणा पै ने न्यायमूर्ति एस.एस. शिंदे और न्यायमूर्ति एन.जे. जामदार की पीठ को बताया कि राज्य सरकार ने उस समय से स्वामी के संपूर्ण चिकित्सा दस्तावेजों का एक संकलन जमा करा दिए हैं, जब से वह एक विचाराधीन कैदी के तौर पर तलोजा जेल में लाए गए थे। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण

(एनआईए) ने अक्टूबर २०२० में स्वामी को रांची से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के समय एनआईए ने उनसे पूछताछ की थी, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी ने कभी उनकी हिरासत नहीं मांगी। पार्किंसन और कई दूसरी बीमारियों से ग्रस्त स्वामी तब ८३ वर्ष के थे। इस साल ५ जुलाई को हाई कोर्ट को स्वामी की मौत की सूचना देने के बाद पीठ में आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ वकील मिहिर देसाई ने बताया था कि स्वामी की मौत एनआईए और महाराष्ट्र जेल प्राधिकारियों द्वारा बरती गई लापरवाही के कारण हुई है, जो उन्हें समय पर पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में विफल रहे। देसाई ने हाई कोर्ट से अनुरोध किया था कि स्वामी की चिकित्सा आधार पर जमानत की याचिका और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत जमानत पर रोक को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को लंबित रखा जाए। उन्होंने हाई कोर्ट से स्वामी के चिकित्सा दस्तावेज मंगवाने का भी अनुरोध किया था। देसाई के अनुरोध पर हाई कोर्ट ने प्राधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की सचाई का पता लगाने के लिए पै ने मंगलवार को बताया कि तलोजा जेल के अधिकारियों ने स्टैन स्वामी को जेल लाए जाने के समय से लेकर उनके पोस्टमॉर्टम तक के चिकित्सा दस्तावेज का ३०० पृष्ठ का संकलन जमा करा दिया है।

२४ घंटे शूटिंग का प्रस्ताव नामंजूर, उद्धव ठाकरे और प्रोड्यूसर्स गिल्ड की बैठक में नहीं बनी बात

मुंबई- महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से शनिवार के दिन फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड के सदस्यों ने बैठक की। प्रोड्यूसर गिल्ड के सदस्यों की मांग थी कि उन्हें महाराष्ट्र में २४ घंटे शूटिंग की इजाजत दी जाए। हालांकि उद्धव ठाकरे ने थर्ड

वेव के संभावित खतरे को देखते हुए उनकी इस मांग को खारिज कर दिया है। फिलहाल शूटिंग समय सुबह ७ से दोपहर ४ बजे तक ही है। सीएम के साथ हुई इस ऑनलाइन बैठक में प्रोड्यूसर्स गिल्ड के रितेश सिधवानी, मधु भोजवानी, राकेश मेहरा, नितिन अहूजा, वहीं मराठी फिल्म इंडस्ट्री के सैराट के डायरेक्टर नागराज मंजुले, सुबोध भावे, रवी जाधव मौजूद थे।

सीएम के इस फैसले से बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स गिल्ड के सदस्य नाराज बताए जा रहे हैं। सीएम के साथ हुई इस बैठक में गिल्ड के सदस्यों के साथ पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले, कोविड टास्क फोर्स के डॉ.संजय ओक, डॉ.शशांक जोशी,डॉ.प्रदीप व्यास भी शामिल हुए थे। कोरोना महामारी के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने शूटिंग के लिए सुबह ७ बजे से लेकर शाम ४ बजे तक की इजाजत दी है। किसी भी शूटिंग के लिए पहले पुलिस की परमिशन लेना अनिवार्य है। इसके अलावा कोविड१९ प्रोटोकॉल का भी पालन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मीटिंग के दौरान यह स्पष्ट किया कि शूटिंग पर मौजूद रहने वाले क्रू मेंबर के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी फिल्म प्रड्यूसर की रहेगी।

जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का विरोध करने पर भाजपा को बिहार में समर्थन वापस ले लेना चाहिए –राउत

मुंबई- शिवसेना सांसद संजय राउत ने जनसंख्या नियंत्रण पर उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्तावित मसौदा विधेयक का रविवार को स्वागत किया और कहा कि यदि जनता दल यूनाइटेड (जदयू) इस विधेयक का विरोध करती है तो भाजपा को बिहार में नीतीश कुमार नीत सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए।

जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के मसौदे के मुताबिक उत्तर प्रदेश में दो से अधिक बच्चे होने पर स्थानीय चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने और किसी भी तरह की सब्सिडी प्राप्त करने के लिए प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव है।

शिवसेना के मुखपत्र 'सामना' में प्रकाशित साप्ताहिक स्तंभ में राउत ने सवाल किया कि क्या विधेयक ईमानदार इरादे से लाया गया है और कहा कि यह मुद्दा (जनसंख्या नियंत्रण) जाति, धर्म और राजनीति से परे होना चाहिए। सामना के कार्यकारी संपादक राउत ने लिखा, "राम मंदिर के मुद्दे का समाधान हो चुका है

इसलिए अब इस मुद्दे पर मतदान करने के लिए नहीं कहा जा सकता। ऐसा कहा जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का उद्देश्य विधानसभा चुनाव (अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले) से पहले ध्रुवीकरण करने के उद्देश्य से लाया गया है।" उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस विधेयक का विरोध करते हुए इसे ' मुस्लिम विरोधी' करार दिया है।

राउत ने ध्यान दिलाया कि उत्तर प्रदेश और बिहार की आबादी करीब १५ करोड़ है और अधिकतर लोग दूसरे राज्यों में जीविकोपार्जन के लिए पलायन करते हैं। उन्होंने कहा कि इन राज्यों में आबादी के नियंत्रण के लिए कानूनी कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने लिखा, "(उप्र के मुख्यमंत्री)योगी आदित्यनाथ को इस पहल के लिए बधाई दी जानी चाहिए और अगर नीतीश कुमार इसका विरोध करते हैं तो भाजपा को बिहार में समर्थन वापस ले लेना चाहिए।" वर्ष १९४७ में भारत के विभाजन को याद करते हुए राउत ने कहा कि देश पंथनिरपेक्ष राज्य (देश) बना ," जहां हिंदुओं को धर्मनिरपेक्षतावादी बनकर रहने पर मजबूर किया गया जबकि मुस्लिम और अन्य धर्मों ने धार्मिक आजादी का आनंद लिया।"

पीपीपी मॉडल से बदलेगा चेहरा...दादर स्टेशन पर रेलवे का फैमिली मॉल

मुंबई- भारतीय रेलवे में पीपीपी मॉडल के साथ ही स्टेशनों का चेहरा बदलने जा रहा है। इस बदलाव में मुंबई के स्टेशन भी शामिल हैं। मुंबई सेंट्रल, अंधेरी के बाद अब पश्चिम रेलवे ने दादर स्टेशन के कायाकल्प की तैयारी शुरू कर दी है। भविष्य में इस स्टेशन पर स्पा, सलून और गेमिंग जोन के साथ ही डोमेस्टिक और मल्टी नेशनल रिटेल ब्रैंड्स की दुकानें दिखाई देंगी। इस संकल्पना को रेलवे ने फैमिली मॉल का नाम दिया है।

रेलवे द्वारा कमाई बढ़ाने के लिए अलग-अलग मॉडल पर काम किया जा रहा है। विभिन्न शहरों में अपनी जमीन पर पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इकॉनमिकल सेंटर डिवेलप किये जा रहे हैं। दादर के फैमिली मॉल सेंटर को रेलवे द्वारा ५०८.४६ वर्ग मीटर के क्षेत्र में डिवेलप किया जाएगा।

इस फैमिली मॉल से ५ साल में रेलवे को ११ करोड़ रुपये रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है। इससे पहले मुंबई सेंट्रल, अंधेरी, कांदिवली, गोरेगांव

और बोरीवली में भी यूनिसेक्स सलून की योजना बनाई है। मुंबई सेंट्रल के वेटिंग रूम एरिया में तो मसाज और स्पा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। इस तरह की सुविधाएं दादर फैमिली मॉल सेंटर में भी उपलब्ध होंगी। नवी मुंबई में बने स्टेशनों की तर्ज पर ही अन्य स्टेशनों को डिवेलप किया जाएगा। यहां निजी कंपनियां शॉपिंग प्लाजा, सिक्योरिटी बूथ, पैसेंजर वेटिंग एरिया, एटीएम कीऑस्क, गेमिंग जोन इत्यादि बनाएंगी।

रेलवे अधिकारी के अनुसार, मौजूदा कोरोना हालात के कारण कोई भी निजी कंपनी बड़े निवेश से बच रही है। बहरहाल, रेलवे की तरफ से जुटाए जा रहे फंड को गैर किराया राजस्व की श्रेणी में रखा जा रहा है। मुंबई उपनगरीय क्षेत्र से ही रेलवे को करीब १०० करोड़ का राजस्व मिलने की उम्मीद है। कैटरिंग और विज्ञापन की कमाई को बढ़ाने के लिए भी रेलवे जोर लगा रही है। मुंबई रेलवे विकास निगम ने २०१४ में एक सर्वे किया था।

किफायती घरों के लिए म्हाडा की नई योजना!

मुंबई- सरकार ने म्हाडा को अफोर्डेबल हाउसिंग का सपना पूरा करने का जिम्मा सौंपा है, लेकिन म्हाडा के पास मुंबई में जमीन बेहद कम है। इसीलिए म्हाडा ३० साल पहले एयर इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व अन्य कंपनियों को आवंटित करीब १०० प्लॉट वापस लेने की तैयारी में है। इस योजना पर म्हाडा ने काम शुरू कर दिया है। इसके तहत चारकोप, गोराई, मालवणी व अन्य स्थानों पर १०० प्लॉट हासिल कर हजारों किफायती घरों का निर्माण किया जा सकता है। मुंबई इमारत मरम्मत व पुनर्रचना मंडल के सभापति विनोद घोसालकर के अनुसार, कर्मचारियों के निवास स्थान तैयार करने के लिए ३० वर्ष पूर्व एयर इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व अन्य को चारकोप, गोराई, मालवणी व अन्य स्थानों पर प्लॉट अलॉट किए गए थे। लेकिन तीन दशक बीत जाने के बाद

भी प्रॉजेक्ट का काम शुरू नहीं हो पाया है। नागरिकों द्वारा लगातार शिकायतें मिल रहीं हैं कि वर्षों से खाली पड़े प्लॉट का विकास नहीं होने से कई प्लॉट पर कचरा फेंका जा रहा है, जबकि कई जगह अतिक्रमण की बात भी सामने आ रही है। इसीलिए म्हाडा ने अपने १०० प्लॉट को वापस लेने का निर्णय लिया है।

श्री हरिहर शिव मंदिर ट्रस्ट ने घोड़माल में किया महिलाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का सुभारंभ

महाराष्ट्र से सटे पालघर जिले के वाड़ा तहसील में स्थित श्री हरिहर शिव मंदिर ट्रस्ट ने घोड़माल गांव में महिलाओं के लिए शिलाई प्रशिक्षण केंद्र का सुभारंभ किया हैं।

इस मौके पर मुख्य ट्रस्टी पुरषोत्तम शर्मा जी ने कहा की इस क्षेत्र की जरूरत मंद महिलाओं को इस केंद्र द्वारा प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर जीवन जीने हेतु सक्षम बनाने का यह उनका प्रयास हैं। इसी उद्देश्य के लिये उन्होंने इस केन्द्र की सुरुवात की हैं।

आगे उन्होंने कहा कि इस केंद्र से आसपास के गांवों की महिलाओं को लाभ मिलेगा और साथ ही यहां से प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत उन्हें ट्रस्ट के माध्यम से रोजगार भी उपलब्ध कराये जाने की योजना हैं।

इस क्षेत्र में ट्रस्ट द्वारा कई प्रकार के सामाजिक कार्य किये जा रहे है जैसे कि कंबल का वितरण, आदिवासी बच्चों को योगा का प्रशिक्षण या उनमे गौसेवा के माध्यम से संस्कार निर्माण करने का कार्य अथवा उनमें स्वक्षता एवं स्वास्थ संबंधी जागरूकता लाना और साथ ही पढ़ाई के साहित्य उन्हें उपलब्ध कराकर शिक्षा हेतु जिज्ञासा उत्पन्न कराना जैसे प्रमुख कार्य पिछले अनेक वर्षों से किये जा रहे हैं।

मराठी फिल्म 'फरफट' की शूटिंग पूरी..!

महेश्वर तेटांबे

तेजस मेघा फिल्म्स प्रोडक्शन मेघा डोळस द्वारा प्रस्तुत और महेश्वर तेटांबे द्वारा निर्देशित, सामाजिक मराठी फिल्म 'फरफट' को हाल ही में औरंगाबाद के गनोरी गांव में शूट किया गया। मेघा डोळस ने फिल्म 'फरफट' के लिए कहानी-पटकथा-संवाद लिखे हैं और महेश्वर तेटांबे ने फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने फिल्म के साथ न्याय करने की पूरी कोशिश की है। संगीतकार अतुल-राहुल ने गीतकार विशाल आडबाल कें गीतोंको संगीत दिया है। डीओपी और संकलन येह दोनों बाजू विनायक जंगम ने सम्भाला हैं । संदीप जाधव ने सहायक निर्देशक और नाना जाधव ने रंगभूषा कार कें रूप में संभाला है। येह कहानी उस माता की हैं जो अपने गतिमंद लडके को सुधारने के लिए क्या क्या नहीं करती। लडका अपनी तरह से कोशिश करता हैं या नहीं। वो कामयाब होता हैं कीं नहीं। ये सारे सवालोंका जबाब यह फिल्म 'फरफट' में चित्रित किया गया है जिसमें मेघा डोळस ने मां की केंद्रीय भूमिका निभाई है और संदीप जाधव मुख्य अभिनेता हैं। साक्षी नाइक, विशाल आडबाल, चंद्रकांत काळे, अक्षदा मोरे, कविता गायकवाड़, विद्या गायकवाड़, सिद्धेश लिंगायत, संतोष तांदले, भाऊसाहेब उबाले, यशवंत मुसले, गुरुनाथ तिरपणकर, प्रमोद दलवी, राहुल शेजूल, अन्नासाहेब (पप्पू) तांदले, दादासाहेब जाधव आदी सभी गनोरी ग्रामस्थ ने भाग लिया। प्रॉडक्शन निर्माण प्रमुख महेंद्र तुपे हैं। निर्माती मेघा डोळस ने विश्वास जताया है कि दर्शकोंको येह सामाजिक फिल्म जरूर पसंद आएगी।

यूपी में कोरोना को लेकर ण्श योगी का बड़ा फैसला- इन ३ राज्यों से आने पर RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट जरूरी

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में अब महाराष्ट्र, केरल व तमिलनाडु आदि राज्यों से आने वालों को कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। योगी सरकार ने तीन प्रतिशत से अधिक कोरोना पॉजिटिविटी दर वाले राज्यों से आने वालों के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट निगेटिव होना जरूरी कर दिया है। तीन प्रतिशत से अधिक पाजिटिविटी दर वाले राज्य महाराष्ट्र, केरल व तमिलनाडु आदि हैं। इसके अलावा केवल वैक्सीन की दो डोज लगवाने का प्रमाण पत्र वालों को ही यूपी में प्रवेश करने की अनुमति होगी। मुख्यमंत्री ने रविवार को टीम-९ के अधिकारियों की बैठक में यह अहम निर्णय लिया। कोविड की तीसरी लहर को रोकने के लिहाज से यूपी सरकार का यह कदम बहुत

महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में कोविड संक्रमण के काफी मामले आ रहे हैं। ऐसे में जिन राज्यों में तीन प्रतिशत से अधिक कोरोना पॉजिटिव की दर हो उन राज्यों से उत्तर प्रदेश में आने वाले लोगों के लिए आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की जाए, जो यात्रा प्रारम्भ होने से चार दिन से अधिक पुरानी न हो। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज प्राप्त कर ली है, उन्हें छूट दी जा सकती है। सड़क,वायु व रेल मार्गो के अलावा निजी साधनों से आ रहे लोगों के लिए भी यह नियम लागू किए जाएं। इन राज्यों से उत्तर प्रदेश आने वाले लोगों की गहन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग की जाए। प्रदेश आगमन पर इनके एंटीजन टेस्ट और थर्मल स्कैनिंग जरूर किए जाएं। इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए जाएं।

महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री कृपाशंकर सिंह ने थामा भाजपा का दामन

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री एवं कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे कृपाशंकर सिंह आखिरकार लंबे इंतजार के बाद बुधवार को भाजपा में शामिल हो गए। दोपहर १२.३० बजे कृपाशंकर सिंह पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर, विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा, की उपस्थिति में औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हुये। सिंह के साथ नासिक जिले के निफाड विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक स्व. रावसाहेब कदम के बेटे यतीन कदम भी आज भाजपा में शामिल हुए हैं।

उनका २०२२ में होने वाले मुंबई मनपा सहित अन्य स्थानीय निकाय चुनावों से पहले भाजपा में शामिल होने से महाराष्ट्र कांग्रेस को बड़ा झटका लगा हैं। क्योकि सिंह मुंबई में उत्तर भारतीय समाज मे अपनी मजबूत पकड़ के लिए

जाने जाते हैं।

वही दूसरी ओर मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान भाई जगताप के रूप में मराठी भाषी व्यक्ति के हाथ होने की वजह से पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीम खान, पूर्व सांसद संजय निरुपम सहित कोई भी बड़ा कांग्रेसी नेता संगठन को मजबूत करने में रूचि नहीं दिखा रहा है। लिहाजा मुंबई में अब कांग्रेस के उत्तर भारतीय वोट बैंक में कृपाशंकर सिंह भाजपा के लिए भारी सेंधमारी कर सकते हैं।

विश्व हिंदू परिषद के साथ-साथ सभी वारकरी संप्रदायों की ओर से राज्य में तीव्र भजन आंदोलन

महाराष्ट्र में पंढरपुर की वारी का विरोध कर एक संत का अपमान करने पर महाराष्ट्र सरकार के विरोध में विश्व हिंदू परिषद सहित पूरा वारकरी समुदाय १७ जुलाई को सड़कों पर उतर आया।

वारी का विरोध, वारकरियों की गिरफ्तारी और उन पर अत्याचार, भागवत ध्वज का अपमान और वरिष्ठ कीर्तनकार एच.बी.पी. बंडातात्या कराडकर की नजरबंदी जैसी घटनाओं का विरोध करने के लिए पूरे महाराष्ट्र में १५४ स्थानों पर भजनी आंदोलन का आयोजन किया गया।

प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप हैकि कोविड नियमों का पालन करते हुए भजन-कीर्तन कर शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने वालों को पुलिस द्वारा कहा गया कि 'आपको अपने भगवान का नाम लेने या भजन करने की अनुमति नहीं है।' साथ ही कई जगह पत्रकारों को रिपोर्टिंग करने से रोक दिया गया था। प्रदर्शन कर रहे वारकरियों एवं विहिप कार्यकर्ताओं का कहना था कि यह सरकार जो हिंदुत्व का इस्तेमाल वोटों के लिए तो करती है परंतु हिंदुत्व का अनादर कर संतों और संविधान में निहित पूरे हिंदू समुदाय की पूजा के अधिकार को कुचलने के लिए सत्ता का गलत उपयोग कर रही है। हम इस सरकार के किसी भी अस्वासन पर विश्वास नहीं करेंगे जो भोले-भाले वारकरियों से बातचीत का बहाना बनाकर उन्हें बेवकूफ बना रही है। अपने भक्तों के दर्शन के लिए तुरंत खड़े रहने वाले विठुमाउली और उनके भक्तों का खुलेआम अपमान किया जा रहा है। क्या हम मौन भजन आंदोलन कर इसका विरोध भी नहीं कर सकते हैं?

इस आंदोलन में भाग लेने वाले वारकरी, साधु संतों ने इस तरह की नाराज़गी व्यक्त की। आगे उन्होंने कहा कि सरकार के इस दमन के जवाब में संत समाज निकट भविष्य में पंढरपुर पैटर्न को पूरे महाराष्ट्र में लागू करेगा।

इस दौरान वारकरियों ने विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन देकर अपनी मांगों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। वरिष्ठ कीर्तनकर एच. बी.पी. बंडातात्या कराडकर और विभिन्न स्थानों पर बाधित सभी वारकरियों को सम्मानपूर्वक रिहा करें। उन पर लगे सभी आरोप तुरंत वापस लिए जाने चाहिए।

गोरेगाँव तीन डोंगरी परिसर में पुलिस-जनता संवाद कार्यक्रम सम्पन्न

मुंबई के गोरेगाँव पश्चिम में समाजसेवक किरण जाधव द्वारा विभाग की समस्त हाउसिंग सोसायटियों एवं सामाजिक संस्थाओं की साथ लेकर सामाजिक स्तर पर एंटी गुंडा स्क्वायड के अधिकारी अमोल बाविस्कर जी के नेतृत्व में प्रभाग में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए एक विशेष पहल की।

जिसके अंतर्गत गोरेगाँव पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारियों एवं स्थानीय रहिवाशियों के बीच एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन ११ जुलाई के दिन चंद्रमणि बुध्दविहार में किया गया। इस आयोजन में प्रभाग के लगभग १८ सोसायटियों एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने शिरकत की।

पास के ही एक कंस्ट्रक्शन साइट के खुले इलाके में पिछले दिनों एक बच्ची के साथ एक नशेड़ी द्वारा घटीत अपराधिक घटना के कारण स्थानीय लोगों में नशेड़ियों के खिलाफ काफी रोष व्याप्त था। किरण जाधव के अनुसार उस वक्त पुलिस अधिकारियों ने गंभीरता से उस विषय पर कार्य किया और अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही करने का अस्वासन भी दिया। और ऐसे विषयों पर जनजागृति हेतु उन्होंने इस संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया ताकि जनता में इन आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए अधिक जागरूता लायी जा सके और अपराधी प्रवित्ति के लोगों को अपराध करने का कोई मौका न मिल पायें। उपस्थित सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय जनता को इस कार्यक्रम के माध्यम से गोरेगाँव पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक हरीश गोस्वामी जी एवं निरीक्षक शिवजी जाधव जी का अपराध रोकने हेतु अमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।

स्थानीय लोगों ने किरण जाधव जी का इस आयोजन हेतु आभार प्रकट किया तथा उनकी काफी सराहना की और कहा कि इस प्रभाग में वे बहुत ही प्रमाणिकता से सभी वर्ग समुदाय के लोगो के लिए सदैव कार्य करते हैं।

पढ़ने वालों के लिए जुटाई हजारों किताबें

पवई- कई बार जिंदगी कुछ कठिन अनुभव भविष्य में कुछ नया करने के लिए प्रेरित करते हैं। मध्यप्रदेश के पन्ना जिले के पवई विकासखंड के शिक्षक सतानंद पाठक की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। बचपन में जब उन्होंने कुछ लोगों को किताबों के अभाव में पढ़ाई छोड़ते देखा तो बाद में भी लोगो को किताबें मुहैया करने लगे। दस हजार किताबों और कोशिश एक कि मुफ्त में किताबें हर जरूरतमंदों को मिले आपने भी किसी को किताब की वजह से पढ़ाई से वंचित होते देखा होगा खासकर गांव में ,जहां ज्यादातर लोग किताब के अभाव में पढ़ाई छोड़ देते है।कुछ ऐसा ही अनुभव रहा सिमरिया गुलाब सिंह के रहने वाले सतानंद पाठक का उन्होंने अपने कई दोस्तों को किताब के अभाव मे पढ़ाई छोड़ते हुए देखा था। जब वे थोड़े बड़े हुए तो गांव के बच्चों को मुफ्त में ट्यूशन पढ़ाने लगे लेकिन किताबों की समस्या तब भी थी । सतानंद पाठक बताते है कि जब वह पढते थे तो उनके दोस्तों के पास पुरानी किताबे खरीदने के लिए पैसे नहीं रहते थे। इसलिए दोस्त बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते थे।कैसे हुई इसकी शुरुआत गांव में ही शिक्षक बन गया फिर निःशुल्क कोचिंग चालू की इससे मुझे और बल मिला और फिर मैंने टैगोर पुस्तकालय के माध्यम से हर जरूरत मंद को किताबे उपलब्ध करवाना चाहता था। इसकी शुरुआत २०१७ मे हुई शुरू मे २०० ही किताबें थी। अब इसमे लगभग दस हजार किताबों का एक कलेक्शन है। जिसमे स्कूल से लेकर कॉलेज सरकारी परीक्षा और साहित्य किताबें शामिल है। शुरू मे मैने खुद किताबें रखी और लोगों के घर जाकर किताबें एकत्रित की अब लोग खुद फोन करके किताबें ले जाने के लिए फोन करते है।सतानंद पाठक कहते है कि लोग यहाँ से एक महीने और एक साल तक के लिए किताबें ले जाते है।

पिछले तीन सालों मे दस हजार किताबे जमा हो चुकी है।

पन्ना जिले से शुरुआत की है और दूसरे लोगो को भी अपने इलाके मे पुरानी किताबें इकट्ठा करके ऐसा ही केन्द्र शुरू करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

फर्जी सर्टिफिकेट से हासिल की यूपी पुलिस में नौकरी, अनबन पर पति ने कर दी शिकायत, सस्पेंड

यूपी के मुरादाबाद जलि में पत्नी के फर्जीवाड़े की शिकायत करना पति को महंगा पड़ गया। नौकरी की उम्र निकलने के बाद एक विवाहिता ने शादी के बाद दोबारा हाईस्कूल और इंटरमीडिएट किया। जब पति ने इसकी शिकायत की तो पुलसि ने जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि महिला ने दोबारा हाईस्कूल-इंटरमीडिएट करने के दौरान अपनी उम्र कम दिखाई है। इसके बाद सिपाही भी बन गई। ऐसे में अब सिविल लाइंस थाने में महिला के साथ ही उसके पति को भी आरोपी बनाया गया है। पुलसि के अनुसार, हरदोई जिले के माधौगंज थाना क्षेत्र के चंपापुरवा गांव निवासी सरोज यादव यूपी पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात हैं। इस समय उसकी तैनाती मुरादाबाद के महिला सिविल लाइंस थाने में चल रही है। पिछले कुछ सालों से उसकी अपने पतर्ि से अनबन चल रही है। इसी विवाद के चलते पिछले साल अक्टूबर माह में महिला सिपाही के पति अरविंद यादव ने एसएसपी को पत्र भेजकर अपनी पत्नी की शिकायत की थी। इसमें आरोप लगाया कि महिला

सिपाही सरोज यादव ने शादी के बाद फर्जीवाड़ा कर अपने प्रमाण पत्रों में नाम बदलकर उम्र कम की है। इसके जरिए उसने पुलिस में नौकरी हासिल कर ली थी। इस शिकायत की जांच सीओ कोतवाली इंदु सिद्धार्थ को सौंपी गई। जांच में सामने आया कि महिला सिपाही सरोज यादव ने शादी के बाद फर्जीवाड़ा करके प्रमाणपत्रों में अपना नाम रीना यादव पुत्री जीत बहादुर जन्मतिथि ६ मई १९९० के स्थान पर सरोज यादव पुत्री जीत बहादुर जन्मतिथि ११ नवंबर १९९२ करा ली। इसके बाद उसने हाईस्कूल, इंटरमीडिएट और बीए किया। इसी प्रमाण पत्रों के आधार पर वह पुलिस विभाग में सिपाही बनी थी। सहायक पुलिस अधीक्षक अनिल यादव ने बताया कि महिला सिपाही और उसके पति के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं महिला सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया गया है। साथ कि महिला सिपाही के पति पर भी केस दर्ज कर लिया गया। बताया जा रहा है। महिला सिपाही का पति शिक्षक था।

आजमगढ़ में पुलिस पर हमला करने वालों पर कार्रवाई के खिलाफ प्रियंका का ट्वीट, यूपी में गरमाई सियासत

आजमगढ़/लखनऊ- आजमगढ़ जिले के रौनापार थानाक्षेत्र के पलिया गांव में करीब एक सप्ताह पूर्व पुलिस के जवानों पर हुए हमले व आरोपियों के घरों में तोड़फोड़ के मामले में कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका के ट्वीट के बाद आजमगढ़ में 'दलित उत्पीड़न' को लेकर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस के अलावा भीम आर्मी और समाजवादी पार्टी भी इस मामले को लेकर आक्रामक है।

कांग्रेस पार्टी दलितों के पुलिस उत्पीड़न के मुद्दे को लेकर दलितों के साथ पलिया गांव में धरने पर बैठ गई है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने १९ जुलाई को पलिया गांव पहुंचकर पीड़ितों को न्याय दिलाने का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि पुलिस पर हमला हुआ है और इस मामले में राजनीति उचित नहीं है।

प्रियंका गांधी वाद्रा ने सोमवार को ट्वीट किया 'आजमगढ़, रौनापार के पलिया गांव में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दलित परिवारों पर हमला करने की खबर आ रही है। वहां कई मकानों को तोड़ा गया, सैकड़ों पर मुकदमा दर्ज किया गया। यह सरकारी अमले की दलित विरोधी मानसिकता का परिचायक है। तत्काल दोषियों के ऊपर कार्यवाही हो और पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए।'

दो दिन पूर्व भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट किया ' जिला आजमगढ़, ग्राम पलिया के प्रधान मुन्ना पासी जी के घर पर की गई तोड़-फोड़ प्रशासन की दलित विरोधी मानसिकता का प्रमाण है। योगी जी दलितों पर आपकी पुलिस द्वारा किया गया अत्याचार दलित समाज भूलेगा नहीं। मैं १९ जुलाई को पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें न्याय दिलाने खुद आजमगढ़ आ रहा हूं।'

ऐसे कसेगी नकेल? नकल कराने वाले कॉलेजों को आगरा विश्वविद्यालय ने फिर बना दिया परीक्षा केंद्र, ३०० आपत्तियां दर्ज

आगरा- उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय पिछली गलतियों से भी सबक नहीं ले रहा है। जिन कॉलेजों में सामूहिक नकल होती पकड़ी गई थी, उन्हीं कॉलेजों को एक बार फिर से परीक्षा केंद्र बना दिया है। परीक्षा समिति के इस निर्णय पर ३५० से ४०० तक आपत्तियां आ चुकी हैं लेकिन केंद्र निर्धारण पर विश्वविद्यालय अधिकारी अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। इरादत नगर के छीतरमल महाविद्यालय में साल २०१९ की परीक्षाओं में सामूहिक नकल पकड़ी गई थी। आईएसएस (इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी) के एक प्रफेसर ने ६ मार्च को उक्त कॉलेज में छापा मारा था। जांच में छात्रों की कॉपियों में एक जैसे उत्तर लिखे थे। इससे सामूहिक नकल की पुष्टि हुई थी। परीक्षा केंद्र से नकल सामग्री भी बरामद हुई थी। इसके अलावा खेरिया के बोहरे नत्थीलाल मुदगल महाविद्यालय, कैला देवी इंस्टीट्यूट आदि कॉलेजों में ना तो प्राचार्य हैं और न ही अनुमोदित शिक्षक हैं। सचल दल की कार्रवाई में इसकी पुष्टि हुई थी। इन्हें फिर से परीक्षा केंद्रों की सूची में शामिल किया गया है।परीक्षा केंद्रों के निर्धारण पर विश्वविद्यालय में ३५० से ४०० के बीच में आपत्तियां आ चुकी हैं। सेल्फ फाइनांस कॉलेज असोसिएशन के सचिव आशुतोष पचौरी का कहना है कि परीक्षा नियंत्रक ने अपनी हठधर्मिता के चलते परीक्षा केंद्रों का चयन किया है, जो कि विश्वविद्यालय के शर्मशार करने वाली बात है। डॉ. अंबेडकर विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षाएं २४ जुलाई से शुरू हो रही हैं। परीक्षाओं के लिए ३६५ परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ३३ नोडल सेंटर बनाए हैं।

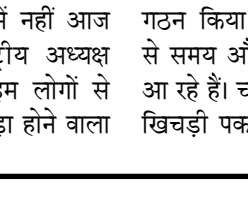

अधिवक्ता ने लगाया BJP MLA के गुर्गो पर मारपीट का आरोप, पति-पत्नी के विवाद पर चल रही थी पंचायत

कानपुर- कानपुर के बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी अक्सर सुखिर्यों में बने रहते हैं। रविवार को अधिवक्ता ने बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी के गुर्गो पर मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ित

अधिवक्ता के बचाव में कई वकील थाने पहुंच गए। अधिवक्ता ने विधायक के गुर्गो के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। दरअसल बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी के घर पर पति-पत्नी के विवाद पर पंचायत चल रही थी। पंचायत में लड़के पक्ष के वकील को विधायक के गुर्गो ने लात-घूंसों से पीट दिया।

बर्रा दो में रहने वाले अधिवक्ता पवन कुमार पांडेय पेशे से वकील हैं। पवन पांडेय ने बताया कि मेरे मुवक्किल शिवम वाजपेई की शादी बीते २४ अप्रैल २०२१ को अंकिता वाजपेई से हुई थी। शादी के बाद पति-पत्नी के बीच विवाद चल रहा है। पत्नी ने शिवम वाजपेई और उसके रिश्तेदारों पर आईपीसी की धारा ४९८, ३२३, ४२७ धारा दर्ज कराया था। पवन कुमार पांडेय ने बताया कि मुकदमा दर्ज होने के बाद किदवई नगर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी के घर पर पंचायत बुलाई गई थी। उनके मुवक्किल शिवम वाजपेई इस पंचायत में उन्हें भी अपने साथ ले गए। दोपहर के वक्त लड़की और लड़के पक्ष के लोग विधायक के ऑफिस में बैठे थे। अधविक्ता ने बताया कि ऑफसि में बैठने के दौरान लड़की पक्ष की तरफ से शोर मचाकर कहा गया कि मैं वीडियो बना रहा हूं। यह सुनते ही विधायक के ४ से ५ गुर्ग आ गए, उन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया और मुझे धक्के मारकर ऑफिस के बाहर ले गए।

शिवपाल यादव की पीएसपी का दावा- २०२२ में बनने वाली सरकार में होंगे शामिल.. चाचा-भतीजे में पक रही खिचड़ी?

कानपुर- उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां सोच-समझकर कदम बढ़ा रही हैं। राजनीति में कब-कौन दुश्मन बन जाए और कौन दोस्त यह कहना मुश्किल है। लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया (प्रसपा) ने सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। पीएसपी दावा कर रही है कि वह २०२२ में बनने वाली सरकार में शामिल होगी। चाचा-भतीजे के बीच सियासी खिचड़ी पकने के भी संकेत मिल रहे हैं।

प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया (पीएसपी) के मुखिया शिवपाल सिंह यादव को राजनीति का माहिर खिलाड़ी माना है। समाजवादी पार्टी में शिवपाल सिंह की भूमिका एक रणनीतिकार के रूप में होती थी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी में होते तो लोकसभा चुनाव २०१९ में एसपी कन्नौज और इटावा की सीट नहीं हारती। पिछले दो दशकों से अपने गढ़ को बचाने के लिए

शिवपाल यादव ही रणनीति तैयार करते थे।पीएसपी के वरिष्ठ नेता और कानपुर के जिलाध्यक्ष अशीष चौबे का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कल में नहीं आज में भरोसा करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने हम लोगों से कहा है कि यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है। जिसे देखकर बीजेपी, बीएसपी, एआईएमआईएम समेत अन्य सभी राजनीतिक पार्टियां हैरान रह जाएंगी। इसके साथ ही उन्होने पूरे आत्मविश्वास से कहा है कि २०२२ में बनने वाली सरकार में हम लोग शामिल होंगे लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले हमें जमीनी स्तर पर तैयारी जारी रखना है।

समाजवादी पार्टी ने साल २०१७ का विधानसभा चुनाव विपरीत परिस्थितियों में लड़ा था। चाचा-भतीजे का परिवारिक विवाद खुले मंचों पर भी देखने को मिला था। शिवपाल सिंह यादव ने खुद को समाजवादी पार्टी से अगल कर लिया था। लोकसभा चुनाव २०१९ से पहले उन्होने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का गठन किया था लेकिन एक बार फिर से समय और हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। चाचा-भतीजे के बीच सियासी खिचड़ी पक रही है।

जर्मनी में बाढ़ का कहर, डूबीं सड़कें-मलबे में तब्दील घर, अब तक १५० से ज्यादा लोगों की मौत

नई दिल्ली- जर्मनी में बाढ़ ने त्रासदी की स्थिति पैदा कर दी है। रविवार को भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में आने के बाद जर्मन शहर बेर्चटेस्गोडेन के आसपास की सड़कें पानी में पूरी तरह से डूब गईं और हर तरफ भीषण जल-जमाव देखने को मिला. समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक दक्षिणी जर्मनी में रविवार को अचानक आई बाढ़ में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और इस सप्ताह देश में आई बाढ़ के बाद तबाही और बढ़ गई, जिसमें १५० से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। ऑस्ट्रिया की सीमा से लगे बवेरिया में जर्मनी का बेर्चटेस्गाडेनर लैंड इलाका भीषण बारिश और बाढ़ से प्रभावित है. बाढ़ और रिकॉर्ड बारिश की कहर से जूझता यह इलाका, मलबे में तब्दील होता दिख रहा है।

रविवार को एक शख्स की मौत के बाद से ही, यह ६ दशकों का सबसे भयावह दौर साबित हुआ है, जब बाढ़ और बारिश जैसी प्राकृतिक आपदा ने १५६ से ज्यादा लोगों की जानें निगल ली हों. वहीं यूरोप में अब तक कुल १८४ लोगों ने जान गंवा दी है।

कोलोन के दक्षिण में सबसे बुरी तरह प्रभावित अहरवीलर इलाके में करीब ११० लोग मारे गए. पुलिस का यह भी कहना है कि जब बाढ़ का पानी सतह से नीचे जाएगा तो शवों के मिलने की आशंका और ज्यादा बढ़ जाएगी. हाल के दिनों में आई बाढ़ ने जर्मनी के राइनलैंड पैलेटिनेट और नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया जैसे राज्यों में भीषण तबाही मचाई है। राइनलैंड पैलेटिनेट और नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया राज्यों के कई हिस्से बिजली

और अन्य संचार साधनों से पूरी तरह से कट चुके हैं, यही वजह है कि लोगों का रेस्क्यू भी कर पाने में मुश्किलें पैदा हो रही हैं. नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया में ही कम से कम ४५ लोग मारे जा चुके हैं।

जर्मनी के वित्त मंत्री ओलाफ स्कोल्ज ने कहा है कि जर्मनी की सरकार तत्काल राहत कार्यों के लिए ३०० मिलियन यूरो से ज्यादा राशि देगी. वहीं ढहे हुए घरों, सड़कों और पुलों को ठीक करने के लिए अलग से रकम आवंटित की जाएगी. वैज्ञानिकों ने काफी अरसे पहले भी आशंका जताई थी कि जलवायु परिवर्तन से भारी बारिश और त्रासदी की स्थिति पैदा हो सकती है। बारिश कब होगी, इसका ठीक पूर्वानुमान लगाने के लिए वैज्ञानिकों को कई सप्ताह का वक्त लगेगा।

बल्ले से पीट-पीटकर ली शराबी पति की जान, आत्महत्या दिखाने के लिए बाथरूम में लटका दिया शव

मुंबई- महाराष्ट्र के मुंबई से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक महिला को शराबी पति की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए, महिला ने उसके शव को बाथरूम की छत से लटका दिया। घटना १२ जुलाई की है, जब राधिका नाम की महिलाा को उसके शराबी पति दीपक सोनार (३६) ने पीटा था। जांच के अनुसार, जब उसने उसे रात को पति को खाना दिया तो उसने प्लेट भी फेंक दी। इसके बाद महिला ने बल्ला उठाकर पति को पीटना शुरू कर दिया।

महिला ने गुस्से में आकर पति को बल्ले से बुरी तरह मारा और कपड़े के टुकड़े से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। जांच में जुटी पुलिस ने बताया कि महिला हत्या के बाद उसके शव को बाथरूम में ले गई और उसे आत्महत्या का रूप देने के लिए वहां लटका दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। उसके शव को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया।

मृतक का शव अंतिम संस्कार के लिए के दौरान उसकी बेटी ने परिवार के सदस्यों को बताया कि उसकी मां ने ही उसके पिता को मार डाला है। बेटी में परिवार के सामने अपनी मां की सारी पोल खोल दी। इस संबंध में परिजनों ने पुलिस से संपर्क किया और महिला को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया।

पृष्ठ 1 से जारी....

मानसून सत्र के लिए...

आयुध कारखानों में हड़तालों को गैर कानूनी बनाते हुए इनमें शामिल होने वाले लोगों के लिए २ साल तक की जेल का भी प्रावधान है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में पराली जलने जैसी घटनाओं से होने वाले प्रदूषण को रोकने वाले बिल पर भी हो हंगामा हो सकता है। दिल्ली सीमा पर आंदोलन कर रहे किसान भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं। अन्य प्रस्तावित नए बिलों में Electricity Amendment Bill , Deposit Insurance & Credit Guarantee Corporation Bill, Coal Bearing Areas (Acquisition) Bill और Pension Fund Regulatory & Development Authority Bill जैसे विधेयक काफी अहम हैं। इसके अलावा लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला बिल भी नए बिलों में शामिल है। Electricity (Amendment) Bill को लेकर भी किसान संगठनों और कुछ राजनीतिक दलों ने विरोध किया है। आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने इस बिल को भी ठंडे बस्ते में डालने की मांग की थी। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो इस बिल का विरोध करेगी। इसके साथ ही मानव तस्करी, खासकर महिलाओं और बच्चों की तस्करी रोकने और तस्करों को सख्त सजा देने वाला बिल भी इसी सत्र में पेश किया जाएगा। वहीं पुराने बिलों में DNA Technology Bill, Data Protection Bill Deewj Maintenance of Senior Citizen Bill भी महत्वपूर्ण हैं।

सर्वदलीय बैठकः सरकार...

सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में सहयोगी अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपति पारस भी सर्वदलीय बैठक में उपस्थित थे। संसद का मानसून सत्र सोमवार को शुरू हो रहा है और १३ अगस्त को इसके समापन की तारीख तय की गई है। संसद सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में शामिल नए मंत्रियों का परिचय दोनों सदनों के सदस्यों से कराएंगे।

यह परंपरा रही है कि नयी सरकार गठित होने या मंत्रिमंडल विस्तार व फेरबदल होने के बाद प्रधानमंत्री नए मंत्रियों का परिचय दोनों सदनों के सदस्यों से कराते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में हाल में बड़ी फेरबदल की गई है। कई नए चेहरे शामिल किए हैं जबकि कुछ मंत्रियों की पदोन्नति कर उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। वहीं, कुछ मंत्रियों का मंत्रालय बदला गया है। वहीं, कुछ सदस्य हाल में हुए उपचुनाव के बाद लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं और सोमवार को वे सदन के सदस्य के तौर पर शपथ लेंगे।

राहत के लिए कारोबारी लगाएंगे राज्यपाल से गुहार, मुख्यमंत्री ठाकरे ने नहीं दिया मिलने का वक्त

मुंबई- राज्य के कारोबारियों को बड़ी उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के 'ब्रेक द चेन' के तहत उन्हें सरकार कुछ तो राहत देगी, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। सरकार ने लॉकडाउन की पाबंदियों को जस का तस जारी रखा है। साथ ही ऐसा कोई संकेत भी नहीं दिया कि कब तक लॉकडाउन के तहत उन पर पाबंदियां लागू रहेंगी। ठाकरे सरकार से नाराज राज्य के कारोबारी अब

गुरुवार को कारोबारियों के नेता राज के. पुरोहित ने व्यापारियों के विविध संगठनों के साथ बैठक की। बैठक में फाम के अध्यक्ष विनेश मेहता, आशीष मेहता, हिंदुस्तान चेंबर के उत्तम जैन, मेटल बाजार के नरसिंह, सुनील पुरोहित, नगरसेवक आकाश राज पुरोहित, जीतू जैन, हितेश कोठारी, महेंद्र जैन, किरीट भंसाली, प्रताप दॉ ंता, गणपति खिरोडी, विश्वास म्हाम्ब्रे, होटल कारोबारी नायर, बीजेपी नेता ओमप्रकाश चौहान, श्याम सप्रे, रमाकांत तिवारी सहित अन्य लोग शामिल हुए। बैठक में कारोबारियों ने कहा कि उन्हें बड़ी उम्मीद थी कि बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार राहत की घोषणा करेगी। दुकानों के समय को शाम ४ बजे से बढ़ाकर रात ८ बजे तक करेगी। साथ की लोकल ट्रेन से उन लोगों को यात्रा करने की छूट देगी, जिनका टीकाकरण हो गया है। संपत्ति कर सहित दूसरे अन्य करों में राहत की घोषणा करेगी, लेकिन ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। उल्टे तीसरी लहर का हवाला देते हुए एक तरह से धमकी दी कि लॉ कडाउन और कड़ा करेंगे। कारोबारियों के नेता राज के पुरोहित ने कहा कि कारोबारियों की हालत बहुत खराब हो गई है। वे अपने घर के जेवर बेचने के लिए मजबूर हो गए हैं। किसी तरह से दुकान चला रहे हैं, लेकिन अब सबकी स्थिति जवाब देती जा रही है। ऐसे में व्यापारियों को राहत नहीं दी गई तो वे खत्म हो जाएंगे। व्यापारियों की समस्याओं को लेकर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी के पास जाएंगे। उनसे गुहार लगाएंगे कि वे मुख्यमंत्री को कारोबारियों की स्थिति से अवगत कराएं। राज ने कहा कि गुजरात जैसे अन्य राज्यों ने लॉकडाउन में बहुत राहत दी है। हमने इस बैठक में निर्णय लिया है कि हम सब व्यापारी एकजुट होकर सरकार के निर्णय का विरोध करेंगे।

फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र यानी फाम के चेयरमैन विनेश मेहता ने कहा कि दुकानदारों को व्यवसाय चलाने के लिए अपने कर्मचारियों को किराया, वेतन आदि का भुगतान करने में कठिनाइयां हो रही हैं। उनकी अपनी बचत समाप्त हो गई है और घर चलाने के लिए गहने बेचने पड़ रहे हैं। कोरोना के चलते लागू पाबंदियों में छूट नहीं दिए जाने से ठाणे शहर के व्यापारियों में राज्य सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ गया है। व्यापारियों ने जिलाधिकारी से पाबंदियों को शिथिल करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे कानून हाथ में लेने को मजबूर होंगे।

भारत समेत कई देशों में पेगासस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर पत्रकारों, ऐक्टिविस्ट की जासूसीः रिपोर्ट

वॉशिंगटन- दुनियाभर के १७ मीडिया संस्थानों की कंसोर्टियम ने दावा किया है कि दुनियाभर में सरकारें पत्रकारों और ऐक्टिविस्टों की जासूसी करा रही है। रविवार को पब्लिश हुई रिपोर्ट के मुताबिक भारत समेत कई देशों में सरकारों ने करीब १८० पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और ऐक्टिविस्ट्स की जासूसी की। इसके लिए इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप के हैकिंग साफ्टवेयर पेगासस का इस्तेमाल किया गया। इस रिपोर्ट में भारत में कम से कम ३८ लोगों के जासूसी का दावा किया गया है।

द गार्जियन ने पेगासस स्पाईवेयर साफ्टवेयर के डेटा का अध्ययन कर दावा किया है कि इस सूची में समाचार वेबसाइट द वायर के एक सह-संस्थापक सिद्धार्थ वरदराजन और वरिष्ठ पत्रकार परंजॉय गुहा ठकुरता का नाम शामिल है। ठकुराता के फोन को २०१८ में हैक कर लिया गया था। गाजिन्यन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उस समय ठकुराता इस बात की जांच कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी सरकार कैसे फेसबुक का इस्तेमाल करके भारतीय लोगों के बीच ऑनलाइन 'गलत सूचना' फैला रही है। रिपोर्ट के अनुसार, लीक हुए आंकड़ों के विशुेषण से पता चला है कि संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला पत्रकार रौला खलाफ, मोरक्को के स्वतंत्र पत्रकार और

मानवाधिकार कार्यकर्ता उमर रेडी और अजरबैजानी खोजी पत्रकार खदीजा इस्मायिलोवा के नाम भी शामिल हैं। रौला खलाफ पिछले साल अखबार के इतिहास में पहली महिला संपादक बनी थीं। २०१८ में जब उनका फोन हैक किया गया तब वह फाइनेंशियल टाइम्स में डिप्टी एडिटर थीं। उमर रेडी सरकार के कई भ्रष्टाचार का खुलासा कर चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि २०१८ और २०१९ के दौरान एनएसओ के इस साफ्टवेयर से उनका फोन हैक किया गया था।

पेगासस एक मैलवेयर है जो आईफोन और एंड्रॉइड डिवाइस को हैक कर लेता है। इससे मैलवेयर भेजने वाला शख्स उस फोन मे मौजूद मैसेज, फोटो और ईमेल तक को देख सकता है। इतना ही नहीं, यह साफ्टवेयर उस फोन पर आ रही कॉल को रिकॉर्ड भी कर सकता है। इस साफ्टवेयर से फोन के माइक को गुप्त रूप से एक्टिव किया जा सकता है। दरअसल, यह डेटा सबसे पहले पेरिस स्थित मीडिया एनजीओ फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल के पास लीक होकर पहुंचा था। बाद में इसे एक रिपोर्टिंग कंसोटिय्म के हिस्से के रूप में वॉशिंगटन पोस्ट, द गाजिन्यन समेत १७ मीडिया संस्थानों के साथ शेयर किया गया। लीक हुए डेटा में ५०००० से अधिक फोन नंबरों की सूची है।

अमेरिका को सता रहा भय, काबुल को अफगानिस्तान से काट सकता है तालिबान

काबुल- अफगानिस्तान में जिस तेजी से तालिबान आतंकी अपने पैर पसार रहे हैं, उससे अमेरिका टेंशन में आ गया है। अमेरिका के खुफिया अधिकारियों ने आशंका जताई है कि तेजी से बढ़ता तालिबान आने वाले समय में काबुल सरकार के भूखों मरने की नौबत ला सकता है। खुफिया सूत्रों ने कहा कि काबुल पर अभी तालिबान के कब्जे का डर नहीं है लेकिन तालिबान राजधानी को देश के अन्य हिस्सों से काट सकता है।

सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के पास अभी इतने संसाधन नहीं हैं कि वह काबुल पर विजय हासिल कर सके। साथ ही अगर तालिबान ऐसा करता है तो उसके ऊपर अमेरिका के हवाई हमले का खतरा रहेगा। खुफिया आकलन में यह भी चेतावनी दी गई है कि तालबिान के आतंकी अगर चाहें तो अफगान सरकार की आयात सप्लाइ लाइन को काट सकते हैं।

उन्होंने कहा कि कई बॉर्डर क्रॉसिंग पर अब तालिबान का कब्जा हो गया है। एक अन्य सूत्र ने संकेत दिया कि तालिबान ने अब तक अपने नियंत्रण वाले बॉर्डर क्रॉसिंग को खुला रखा हुआ है ताकि आयात-निर्यात के माध्यम से होने वाली आय पर कब्जा किया जा सके। उन्होंने कहा कि अफगान सरकार भी बॉर्डर क्रॉसिंग पर कब्जा करने को एक बड़े खतरे के रूप में देखती है। इसी वजह से वह विशेष सैन्य दस्ता बना रही है ताकि उसकी सुरक्षा की जा सके। ये सुरक्षा बल उन जवानों से अलग होंगे जो तालिबान के आने पर भाग खड़े हुए थे। इससे पहले पिछले सप्ताह तालिबान आतंकियों ने अफगान सुरक्षा बलों के सैकड़ों वाहन, छोटे ट्रक, तोपें, मोर्टार, एंटी एयरक्राफ्ट गन आदि पर कब्जा कर लिया था। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर तालिबान को तेल मिल गया तो वह इन वाहनों और हथियारों का इस्तेमाल तेजी से जंग करने में कर सकती है। वहीं एक अन्य अधिकारी ने कहा कि तालिबान केवल तभी काबुल की ओर बढ़ेंगे जब उन्हें भरोसा हो जाएगा कि वे फतह हासिल कर सकते हैं।इस बीच अफगान नैशनल सिक्यॉरिटी फोर्सेज ने शुक्रवार को स्पिन बोल्डक को तालिबान के कब्जे से छुड़ा लिया है। अफगानिस्तान सरकार के सूत्रों ने रूस की न्यूज एजेंसी स्पूतनिक से इस दावे की पुष्टि की है। स्पिन बोल्डक वही जगह है जहां अफगान सुरक्षाबलों पर हमले में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की जान चली गई थी। दानिश काफी वक्त से अफगानिस्तान में तालिबान के साथ बनी युद्ध जैसी स्थिति को कवर कर रहे थे।

मुंबई एयरपोर्ट की कमान हाथ आते ही अडानी समूह ने बदला इस कंपनी का सीईओ, जानिए किसे मिली जिम्मेदारी!

मुंबई- अडानी समूह ने मुंबई हवाईअड्डे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आरके जैन को अपने हवाईअड्डों के व्यवसाय का सीईओ नियुक्त किया है। वह बेन ज़ानदी की जगह लेंगे जो अब अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (एएएचएल) में गैर-हवाई व्यवसाय के सीईओ का काम संभालेंगे। यह बदलाव एएएचएल द्वारा पिछले सप्ताह मुंबई एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएएल) का प्रबंधन जीवेके समूह से लेने के बाद किया गया है। एएएचएल अडानी समूह की सहायक कंपनी है जो हवाई अड्डों के कारोबार से जुड़ी है। १७ जुलाई को जारी एक सूचना के अनुसार एएएचएल के अध्यक्ष (परिचालन) प्रकाश तुलसियानी मुंबई हवाईअड्डे के सीईओ का कार्यभार संभालेंगे।

कुछ लोग अराजकता फैलाने के लिए तालमेल बिठाकर कर रहे काम : BJP

नई दिल्ली- भाजपा ने रविवार को कहा कि कुछ लोग देश में भ्रम और अराजकता फैलाने के उद्देश्य से पूरी तरह तालमेल बिठाकर काम कर रहे हैं। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने कहा,

'एक पोर्टल, न्यूजक्लिक, जो मीडिया हाउस के रूप में चित्रित करने की कोशिश करता है, ने केवल एक उद्देश्य के साथ संदिग्ध तरीके से करोड़ों रुपये प्राप्त किए, भारत की प्रणाली को विफल के रूप में चित्रित करने के लिए और देश में कुछ विदेशी शक्तियों का प्रचार-प्रसार करने के लिए।' पात्रा ने दावा किया कि देश में एक समूह है जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत देश को खराब रोशनी में दिखाने का काम कर रहा है। पात्रा ने कहा, 'मीडिया के नाम पर पोर्टल चलाने वाले कुछ कार्यकर्ता हैं, जिनके साथ कुछ विदेशी ताकतें हैं और कुछ मुख्यधारा के राजनेता हैं जिन्होंने हाथ मिलाकर एक समूह बनाया है। वे देश में भ्रम और अराजकता फैलाने के उद्देश्य से काम करते हैं।' पात्रा ने दावा किया कि न्यूजक्लिक के मामलों में सामने आए तथ्य बताते हैं कि टूलकिट को न केवल देश में कुछ राजनीतिक दल चला रहे हैं, बल्कि इस टूलकिट के हिस्से के रूप में भारत के बाहर भी एक साजिश चल रही है।

दिल्ली में कोरोना ने तोड़ा दमः पांच महीने बाद नहीं हुई एक भी मौत, ५१ नए संक्रमित आए सामने

राजधानी में रविवार को पांच महीने बाद कोरोना से होने वाली दैनिक मौतों का आंकड़ा शून्य रहा। इससे पहले १७ फरवरी को कोरोना से कोई मौत नहीं हुई थी। उसके बाद से यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा था और तीन मई को में ४४८ तक पहुंच गया था। अब पिछले करीब दो सप्ताह से मौत की संख्या कम हो रही है। बीते आठ दिनों में १० लोगों ने संक्रमण से जान गंवाई है। विशेषज्ञों का कहना है कि दैनिक मृतकों की संख्या शून्य पर आना एक बड़ी राहत है। हालांकि लगातार सतर्क रहने की जरूरत है।

दिल्ली में मार्च के आखिरी सप्ताह में दूसरी लहर आई थी। तब अप्रैल में सक्रिय मरीजों की संख्या करीब एक लाख हो गई थी। इस कारण अस्पताल भी पूरी तरह भर गए थे और घर पर इलाज कराने वालों की संख्या भी ५०

हजार के पार पहुंच गई थी, तब महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक सक्रिय मरीज दिल्ली में ही थे। यहां जितने तेजी से महामारी फैली थी। उतनी ही तेजी से कम भी हुई। आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल मई में जहां प्रतिदिन २०० से अधिक मौतें हो रही थीं अब एक सप्ताह से यह आंकड़ा ०१ रह गया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, रविवार को कोरोना के ५१ नए मरीज मिले। इस दौरान ८० मरीज स्वस्थ हुए। पिछले २४ घंटों मे ७१,५४६ नमूनों की जांच की गई है, जिनमें ०.०७ फीसदी सैंपल संक्रमित मिले। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या १४,३५,५२९ है, जिनमें से अब तक १४,०९,९१० मरीज स्वस्थ हुए हैं। जबकि, कुल मौत का आंकड़ा २५,०२७ है। सक्रिय मरीजों की संख्या ५९२ रह गई है। २०३ रोगी अपने घरों में आइसोलेशन में हैं।

'संकल्प प्रभात'साप्ताहिक मालिक, मुद्रक, प्रकाशक - अनिल बी. तिवारी द्वारा सोमानी प्रिंटींग प्रेस, गाला नं. ३/४, अमीन इंडस्ट्रीयल इस्टेट, सोनावाला'हॉस रोड नं. २, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- ४०००६३, महाराष्ट्र. से मुद्रित कर ९४/४ नाथुमल सोसायटी, यशवंत नगर, रोड नं. २, नियर गणेश टेम्पल, तीनडोंगरी, गोरेगाव (पश्चिम), मुंबई- ४०० १०४ से प्रकाशित. संपादक - अनिल बी. तिवारी
• RNI No.: MAHHIN/2016/71344 • Mob.: 98205 50990/90043 30234 • Email: sankalpprabhat@gmail.com • Website:www.sankalpprabhat.com